



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2006 (अग्रहायण 11, 1928)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2006 (AGRAHAYANA 11, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 15 नवम्बर 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, अक्टूबर 2006 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात को विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

#### सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
कुछ नहीं					

#### सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
कुछ नहीं					

जीपीएच वी.सी.एन. 021558	रु. 1,00,000/-	इंद्राहीम बुशेरी पाशाह बुशेरी (कोई एक या उत्तरजीवी)	19/4/2000	इंद्राहीम बुशेरी पाशाह बुशेरी	06.25.93 10.05.2005
----------------------------	----------------	---	-----------	----------------------------------	------------------------

आर.जी. भिवंडकर  
सहायक प्रबंधक

### भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 8 नवम्बर 2006

एसबीडा क्र. 09/2006-07--भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के निर्बंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री पी.पी. पटनायक को कार्यग्रहण तिथि से 31 जनवरी 2009 तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

ओम प्रकाश भट्ट  
अध्यक्ष

### श्रम मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. पी-IV/2(6)/84/क.भ.नि. स्टाफ (सी.सी.ए.) नियमावली, 1971/बोल्यूम-II-कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1971 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2006 कहलायेंगे।  
(ii) ये सरकारी राजात्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1971 के नियमों/उपनियमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाए जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है:--  
(क) नियम 7(iii) (क) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए:--  
“क्यूमिलेटिव प्रभाव के बिना तथा उसकी पेंशन में प्रतिकूल प्रभाव के बिना, सावधिक वेतनमान में निम्न चरण (लोवर स्टेज) में एक चरण (स्टेज) घटाना जोकि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी”  
(ख) नियम 6 के उप-नियम 5 (ग) के बाद उप-नियम (6) तथा (7) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए:--  
(6) इस नियम के अंतर्गत किए गए निलंबन या किए जाने वाले निलंबन की समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित

समीक्षा समिति की सिफारिश पर निलंबन में संशोधन करने या बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा निलंबन की अवधि बढ़ाने या निलंबन करने के लिए आदेश पारित करेगी। निलंबन की बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से पूर्व पुनः समीक्षा की जाएगी। निलंबन की बढ़ाई गई अवधि एक समय में एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी।

- (7) उपनियम 5(क) में अन्य बातों के होते हुए भी इस नियम के उप नियम (1) या (2) के अंतर्गत किया गया निलंबन या किए जाने वाला निलंबन नब्बे दिन की अवधि के बाद वैद्य नहीं होगा यदि नब्बे दिन की अवधि समाप्ति से पूर्व समीक्षा के बाद अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है।
- (ग) नियम 10 में उपनियम (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए:--

“यदि केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3-ग में निहित अर्थ के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की शिकायत है तो ऐसी शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति, इन नियमों के उद्देश्य के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माने जायेंगे, यदि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है तो शिकायत समिति इन नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक हो सके व्यावहारिक जांच करेगी।

आ. विश्वानाथन  
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

### राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. फा. 47-49/2006-राअशिप/समन्वय--राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 20(3) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 47-5/2003/राअशिप/समन्वय के माध्यम से निम्न सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों के लिए नामित किया गया था:--

- (i) उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर

प्रोफेसर ए. के. शर्मा, ए-18, सेक्टर-33, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

## (ii) दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलोर

प्रोफेसर (श्रीमती) एम.एस. गोमती अम्मल, 150, चैत्रा गांधी नगर, तिरुवनंतपुरम्, केरल।

## (iii) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल

डाक्टर (सुश्री) हेमलता एन. परसनीस, प्रोफेसर तथा संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई।

## (iv) पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर

सुश्री शुभ्रा चैटर्जी, विक्रमशिला एजूकेशन रिसोर्स सोसायटी, 77, महाराजा टैगोर रोड, ढकुरिया, कोलकाता-700031

1. प्रोफेसर ए.के. शर्मा, प्रोफेसर (श्रीमती) एम.एस. गोमती अम्मल तथा डा. हेमलता एन. परसनीस की सदस्यता क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय समितियों से इस कारण रद्द की जाती है क्योंकि वे भारत के राजपत्र में 24.02.1996 को प्रकाशित राइशिप के दिनांक 26.12.1995 के विनियम संख्या फा. 28-4/95-राइशिप के खंड 3(च) के साथ पठित राइशिप अधिनियम 1993 के खंड 20(3) के अधीन यथा अपेक्षित परिषद् के सदस्य नहीं हैं।

वी.सी. तिवारी  
सदस्य सचिव

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

## (माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 नवम्बर 2005

पत्र सं. एफ-27/12/2004-डेस्क (यू) डि:--निम्नलिखित संविधि निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

1. स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन के कार्य।

2. विभाग प्रमुख के दायित्व।

3. मानद् प्रोफेसर व अवकाश प्राप्त प्रोफेसर की सेवा शर्तें।

4. परिषक्क एवम् मॉडरेटर की नियुक्ति।

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 (1997 की सं. 2) के अनुसार ये नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवम् संसद के प्रत्येक सदन के सक्षम प्रस्तुत होंगे।

## नियम

## स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन के कार्य

[एक्ट एस 27 (1) (क्यु) व संविधि 7 (3)]

विश्वविद्यालय के नियम 27 (1) (क्यु) व संविधि 7 (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद की अनुशंसा के अनुसार, विश्वविद्यालय स्कूलस् के डीन के सम्बन्ध निम्न लिखित संविधि निर्माण करती है।

1. स्कूलस् के डीन उस स्कूल के प्रमुख होंगे और स्कूलस् में शिक्षण व शोध कार्य कराने में शिक्षण एवम् शोध के प्रतिमान बनाए रखेंगे। वह स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष व संयोजन होंगे।

2. डीन की निम्नलिखित शक्तियां व कार्य होंगे:--

(a) विभाग एवम् केन्द्र प्रमुख के जरिए स्कूल के शिक्षण एवम् शोध कार्य संयोजन व सामान्य निरीक्षण कराना।

(b) जहां कहीं आवश्यक हो अंतर विभाग शिक्षण एवम् शोध को बढ़ावा देने के कदम उठाना।

(c) जहां कहीं विहित किया गया हो छात्रों की संत्रीय कार्य के मूल्यांकन एवम् लेक्चर, ट्युरोरियल/सेमिनार व प्रयोगिक कक्षाओं में उपस्थिति का रिकार्ड रखना।

(d) अकादमिक परिषद के बोर्ड ऑफ स्कूल के निर्देशों के अनुसार स्कूल के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराना।

(e) स्कूलस् के निर्णयों एवम् अनुशासाओं को कार्य रूप देने हेतु कदम उठाना।

(f) अन्य कोई कर्तव्य का निर्वाह जो अकादमिक परिषद् कार्यकारी परिषद् या उपकुलपति द्वारा किया गया हो।

## विभाग प्रमुख के कर्तव्य

[अधिनियम एस. 27 (1) (क्यु) नियम 8 (5)]

विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुभाग 27 (1) (क्यु) की संविधि 8 (5) के अधीन अधिकारों के तहत, कार्यकारी परिषद् जैसा एकादमिक परिषद् ने संविधि अनुसंशित की है। विश्वविद्यालय के विभाग प्रमुख के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम का निर्माण करती है।

\* विभाग या केन्द्र का प्रमुख डीन की देखरेख में विभाग/केन्द्र की बैठक का आयोजन करेगा एवम् उसकी अध्यक्षता करेगा।

अ. विभाग/केन्द्र के शिक्षण व शोध कार्यों का आयोजन करेगा।

ब. विभाग या केन्द्र द्वारा नियम शिक्षण कार्य को बांटने के परिणाम स्वरूप टाइम टेबल बनाएगा।

स. शिक्षकों के माध्यम से कक्षा एवम् प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखेगा।

द. विभाग/केन्द्र के उपयुक्त क्रियाकलाप हेतु शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित करेगा व विभाग/केन्द्र के गैर शैक्षिक कर्मचारियों के कार्यों को निर्धारित करेगा व उन पर नियंत्रण रखेगा। एवम्

इ. ऐसा कोई भी कार्य करेगा जो उसे सम्बन्धित बोर्ड आफ स्कूल के डीन, अकादमिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् या उपकुलपति द्वारा करने को कहा गया हो।

मानद् प्रोफेसर व अवकाश प्राप्त प्रोफेसर की नियुक्ति की शर्तें

[अधिनियम एस 5(XV), 27 (1) (q)]

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुभाग 27 (1) (q) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अधीन, अकादमिक परिषद् द्वारा अनुशंसाओं पर कार्यकारी

परिषद्, मानद् प्रोफेसर व अवकाश प्राप्त प्रोफेसर की नियुक्ति की सेवा शर्ते सम्बन्धी निम्नलिखित नियम का निर्माण करती है।

#### मानद् प्रोफेसर

1. एक ऐसा स्कॉलर जो या तो सेवा में हो या सेवा निवृत्ति पर, डॉन ऑफ स्कूलस या उपकुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद् द्वारा मानद् प्रोफेसर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है।
2. नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी।
3. मानद् प्रोफेसर को कोई वेतन या मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा, हर दशा में उन्हें स्थानीय सत्कार व यात्रा खर्च उनके निवास स्थान से विश्वविद्यालय तक का देय होगा, जब कभी पुनः वह भी उन्हें व्याख्यान देने हेतु या किसी अन्य अकादमिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु विश्वविद्यालय आना हो।

#### अवकाश प्राप्त प्रोफेसर

1. एक प्रोफेसर जो विश्व विद्यालय से सेवा निवृत्त हो चुका हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा उसकी शिक्षण/शोध कार्य को जारी रखने हेतु सेवा निवृत्ति पश्चात् अवकाश प्राप्त प्रोफेसर (अमीरेट प्रोफेसर) के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।
2. नियुक्ति तीन वर्षों के लिये होगी व नवीनीकरण भी हो सकेगा।
3. अवकाश प्राप्त प्रोफेसर को कोई वेतन या मानदेय देय नहीं होगा।
4. उसे, उसके कार्यकाल के दौरान उसके शिक्षण एवं शोध कार्य चलाने हेतु कार्यालय स्थल एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे।

#### परीक्षकों एवं मार्डरेटर्स की नियुक्ति

[अधिनियम एस 27 (g), नियम 13 (2) (xiii)]

विश्वविद्यालय के अनुभाग 27 (g) के नियम 13 (2) (xiii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन, कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद के प्रस्ताव पर निम्नलिखित परीक्षकों एवं मार्डरेटरों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों का निर्माण करती है।

1. समस्त परीक्षकों के परीक्षकों एवं मार्डरेटरों की सूची, पी.एच.डी. उपाधि को छोड़कर जो सम्बन्धित विभाग के बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा बनाई जाएगी व सम्बन्धी स्कूल आफ स्टडीज को प्रस्तुत की जाएगी। सम्बन्धित स्कूल आफ स्टडीज सूची को जांचकर, अकादमिक परिषद् की सलाह से कार्यकारी परिषद की स्वीकृति हेतु इसको अप्रेषित करेगा।
2. पी.एच.डी. उपाधि के परीक्षकों की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा, सम्बन्धित बोर्ड ऑफ स्टडीज की अनुशंसा पर अकादमिक परिषद की राय से करेगी।
3. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषयों के प्रश्न पत्रों का माडरेशन जा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हो, निम्न सदस्यों की समिति करेगी।
- अ. सम्बन्धित विभाग के प्रमुख एवं
- इ. उपकुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त कोई दो व्यक्तियों से अधिक व एक व्यक्ति से कम न हो।
- बशर्ते मार्डरेटर्स में से एक सम्बन्धित परीक्षा का परीक्षक हो सकेगा जो विश्व विद्यालय में शिक्षण कार्य में नहीं लगाया गया हो।
4. प्रश्न पत्र नियमों के अनुसार मार्डरेट होंगे।

#### ५. अ. बाहरी परीक्षकों को फीस की दरे एवं शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगी

परीक्षा का माप	एक पेपर बनाने के द्वारा प्रति पेपर	एक उत्तर पुस्तिका बनाने के द्वारा Rs/प्रति उत्तर पुस्तिका	सत्रीय कार्य बनाने के द्वारा प्रति पुस्तिका	उत्तर पुस्तिका की बनाने प्रति पुस्तिका	मार्डरेशन प्रति पुस्तिका	गोदावक परीक्षण के द्वारा प्रति शास्र रुपयोगी
स्नातक	Rs 200	Rs 7	Rs 4	Rs 0.20 n.p..	Rs 15/-	-
स्नातकोत्तर (व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित)	Rs 200	Rs 8	Rs 5	Rs 0.20 n.p.	Rs 20	2.50 Rs 50/-
मुख्य परीक्षक के बुनाना			प्रति शास्र 200 रुपये एवं 10 प्रतिशत के जाकलिंग जांच के 7 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका			
कोडिन व डिकोडिन			Rs 0.25 n.p. प्रति उत्तर पुस्तिका			
ग्रनाइटम देतु			Rs 100 रुपये प्रतिशिल्प			
एम. किल.			जो दो का आकलन 300 रुपये			
पी.एस. डी.			75 रुपये			
			500 रुपये			
			150 रुपये			

ब. यदि एक परीक्षा बोर्ड एक प्रश्न पत्रों का सेट तैयार करता है एवम् उत्तर पुस्तिका का आकलन करता है तो प्रत्येक परीक्षक को पूरा भुगतान देय होगा जो कालम II व III में विहित है।

स. जब कहीं एक उत्तर पुस्तिका दो परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से जांची गई हो तो प्रत्येक परीक्षक को उपरोक्त कालम III में निर्धारित पूरा मानदेय देय होगा।

द. किसी विषय में यदि प्रश्न पत्र दो अलग-अलग भागों में दो बाहरी परीक्षकों द्वारा अलग-अलग बनाया गया हो तो उसकी उत्तर पुस्तिकाएं भी एक दूसरे से अलग-अलग स्वतंत्र रूप से जांची गई हो तो प्रत्येक परीक्षक का कालम II व III में विहित दरों का 3/5 प्रत्येक को प्रश्न पत्र बनाने एवम् उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु देय होगा।

भुगतान की दरें II में विहित दरों से कम से कम प्रश्न पत्र बनाने हेतु संबंधित विषय की परीक्षा की आधी दर से कम नहीं होगी।

फ. यदि माडरेशन समिति द्वारा आधे से अधिक प्रश्न पत्र को बदल दिया जाता है तो उपकुलपति, समिति के संचालन के अनुशंसा पर, कोई भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी कर सकेगा।

ज. यदि दो या दो अधिक परीक्षक मौखिक परीक्षा का संचालन करते हैं तो उनका भुगतान दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा।

ह. जब तक की कुलसंचिव को अंक तालिका, उत्तर पुस्तिकाएं, परीक्षकों की रिपोर्ट या अन्य कोई ऐसा प्रपत्र जो वांछित हो नहीं मिल जाता, भुगतान नहीं हो सकेगा।

ई. ह. में विहित सभी कागजात बाहरी परीक्षक द्वारा एक नियत तिथि तक जमा नहीं करता तो उसके देय भुगतान को प्रथम सात दिनों तक 5 रुपये प्रतिदिन की दर से कम कर दिया जाएगा व दस रुपये प्रतिदिन उसके पश्चात्। यदि उपकुलपति विलम्ब के बारे में परीक्षक के नियंत्रण से परे कारणों से संतुष्ट नहीं हो जाता।

जे. परीक्षकों को देय भुगतान समय-समय पर पुनः निर्धारित किये जा सकेंगे।

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 8th November 2006

SBD No. 09/2006-07—In terms of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Mysore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri P.P. Pattanayak as Managing Director of State Bank of Mysore upto 31st January 2009 with effect from the date he assumes charge.

O. P. BHATT  
Chairman

## DEPARTMENT OF GOVERNMENT &amp; BANK ACCOUNTS

## CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 15th November 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended October 2006 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

## List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Byculla, Mumbai Circle 9% Relief Bonds 1999 (Demat)					
NIL					

## List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Byculla, Mumbai Circle 9% Relief Bonds 1999 (Demat)					
GPH BCN 021558					
Rs. 1,00,000		Ebrahim Busheri & Pashah Busheri (Either or Survivor)	19/4/2000	Ebrahim Busheri & Pashah Busheri	06.25.93 10.5.2005

R. G. BHIWANDKAR  
Asstt. Manager

**MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANIZATION**

New Delhi-110 066, the 10th November 2006

No. P-IV/2(6)84/Employees' Provident Fund Staff (CCA) Rules, 1971/Vol-II—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 7(a) of Section 5D of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) Central Board, makes the following rules and further amends the Employees' Provident Fund Staff (Classification, Control and Appeal) Rules, 1971 namely :—

1. (i) These rules may be called Employees' Provident Fund Staff (Classification, Control and Appeal) Rules, 2006.  
 (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Provident Fund Staff (Classification, Control and Appeal) Rules, 1971, following entries shall be substituted/inserted in the Rules/Sub-Rules shown as below :—
  - (a) Rule 7 (iii)(a) shall be substituted as follows :—  
 “Reduction to lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding 03 years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension”.
  - (b) Sub-Rule (6) & (7) shall be inserted after Sub-Rule 5(c) of Rule 6 as follows :—  
 (6) An order of suspension made or deemed to have been made under this Rule shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.  
 (7) Notwithstanding anything contained in Sub-Rule 5(a), an order of suspension made or deemed to have been made under Sub-Rule (1) or (2) of this Rule shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review for a further period before expiry of ninety days.
  - (c) In Rule 10, after Sub-Rule (2), the following proviso shall be inserted :—  
 “Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the

Complaints Committee established in each Ministry of department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these Rules and the Complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these Rules”.

A. VISWANATHAN  
Central Provident Fund Commissioner

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**

New Delhi-110 002, the 8th November 2006

No. F.47-49/2006/NCTE/CDN—In exercise of the powers conferred under Section 20(3)(a) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the following members were nominated by the Council to the Regional Committees of the National Council for Teacher Education vide NCTE's Notification No. F. 47-5/2003/NCTE/CDN dated 18th March, 2005.

- (i) Northern Regional Committee, Jaipur.  
 Prof. A.K. Sharma, A-18, Sector-33, Noida-201307, Uttar Pradesh, Northern Regional Committee, Jaipur.
- (ii) Southern Regional Committee, Bangalore.  
 Prof. (Smt.) M.S. Gomti Ammal, 150, Chaitra, Gandhi Nagar, Thiruvananthapuram, Kerala.
- (iii) Western Regional Committee, Bhopal  
 Dr (Ms.) Hemlata N. Parasnath, Professor and Dean, Faculty of Education, SNDT Women's University, Mumbai.
- (iv) Eastern Regional Committee, Bhubaneswar.  
 Ms. Shubra Chatterjee, Vikramshila Education Resource Society, 77, Maharaja Tagore Road, Dhakuria, Kolkata-700 031.

2. The Membership of Prof. A.K. Sharma, Prof. (Smt.) M.S. Gomti Ammal and Dr. Hemlata N. Parasnath stands cancelled from the Northern, Southern and Western Regional Committees respectively as they are not members of the Council as required under Section 20(3) of the NCTE Act, 1993 read with Section 3(f) of the NCTE Regulation No. F.28-4/95-NCTE dated 26.12.1995, published in the Gazette of India on 24.02.1996.

V. C. TEWARI  
Member Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY  
(DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND  
HIGHER EDUCATION)**

New Delhi-110 001, the 21st November 2006

No. F.27-12/2004-Desk(U)—'NO OBJECTION' to the framing of the following Ordinances :—

1. Functions of Deans of Schools of Studies
2. Duties of Heads of Department
3. Terms and Conditions of Appointment of Honorary Professors and Emeritus Professors
4. Appointment of Examiners and Moderators

In terms of Section 43 of Maulana Azad National Urdu University Act, 1996 (No. 2 of 1997) these Ordinances are to be published in the Official Gazette and also to be laid before each house of the Parliament.

**ORDINANCE**

**FUNCTIONS OF DEANS OF SCHOOLS OF STUDIES**  
[Act S. 27(1)(q) Statute-7(3)]

In exercise of the powers vested in Section 27(1)(q) & Statute 7(3) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding Deans of Schools of the University.

1. The Dean of a School shall be the Head of the School and shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the School. He shall be the Chairman and Convener of the Board of the School.
2. The Dean shall have the following powers and functions :—
  - (a) To co-ordinate and generally supervise the teaching and research work in the School through the Head of Departments/Centres;
  - (b) To take steps to promote inter-disciplinary teaching and research, wherever necessary;
  - (c) To keep a record of the evaluation of sessional work and of the attendance of the students at lectures, tutorials, seminars or practicals wherever these are prescribed;
  - (d) To arrange for the examination of the University in respect of the students of the School in accordance with such directions as may be given by the Board of Schools of studies of the Academic Council
  - (e) To take steps to give effect to the decision and recommendations of the School; and

- (f) To perform such other duties as may be assigned to him by the Academic council, Executive Council or the Vice-Chancellor.

**DUTIES OF HEADS OF DEPARTMENT**

[Act S. 27(1)(q) Statute-8(5)]

In exercise of the powers vested in Section 27(1)(q) & Statute 8(5) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding Heads of Department of the University.

The Head of a Department/Centre shall convene and preside over meetings of the Department/Centre, and shall under the general supervision of the Dean :—

- a. organize the teaching and research work in the department/centre;
- b. frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department/Centre;
- c. maintain discipline in the class rooms and laboratories through teachers;
- d. assign to the teachers in the Department/Centre such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department or Centre; and assign work to and exercise control over the non-teaching staff in the Department/Centre; and
- e. perform such other functions as may be assigned to him by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council, the Executive Council and the Vice Chancellor.

**TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF  
HONORARY PROFESSORS AND EMERITUS  
PROFESSORS**  
[Act S. 5(xv), 27(1)(q)]

In exercise of the powers vested in Section 27(1)(q) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding terms and conditions of appointment of honorary Professors and Emeritus Professors of the University.

**HONORARY PROFESSOR :—**

1. A distinguished scholar who is either in active service or on superannuation may be considered for appointment as Honorary Professor by the Executive Council on the recommendation of the Dean of the School or Vice-Chancellor.
2. The duration of appointment shall be 3 years.
3. Honorary Professors will not be paid any salary or remuneration. However, he/she will be provided local hospitality and travel expenses from the place of his/her residence to the University and back whenever he/she visits the University for delivering lectures and for participating in any other academic activity of the School.

**EMERITUS PROFESSOR :—**

1. A Professor who has retired from the University may be invited by the Executive Council to continue his/her research/teaching activities in the University as an Emeritus Professor after his/her superannuation.
2. The duration of appointment shall be 3 years with a provision for renewal.
3. The Emeritus Professor will not be paid any salary or remuneration.
4. He/she will be provided office space and other facilities to carry out his/her research/teaching activities during his/her tenure.

**APPOINTMENT OF EXAMINERS AND MODERATORS  
[Act S. 27(g) Statute 13(2)(xiii)]**

In exercise of the powers vested in Section 27(g) Statute 13(2)(xiii) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding appointment of examiners and moderators of the University.

1. The list of the examiners and Moderators for all examinations, except for Ph.D. degree shall be drawn up by the Board of Studies and submitted to the School of Studies concerned. The School of Studies

shall scrutinize the list and forward the same to the Executive Council for approval in consultation with the Academic Council.

2. The Examiners for Ph.D. Degree shall be appointed by the Executive Council in consultation with Academic Council on the recommendation of the School Board of the School concerned.
3. The question papers for examination in each subject of studies offered by the University shall be moderated by a committee consisting of :
  - a. Head of the Department concerned; and
  - b. Not less than one and not more than two other persons appointed by the Vice Chancellor for the purpose.
- Provided that one of the Moderators may be an Examiner in the concerned examination not engaged in teaching in the University.
4. The question papers shall be moderated in accordance with the regulations;
5. a. The external Examiners shall be paid the fees at the rates and conditions specified below :

I Name of the Exam.	II For setting a paper (Rs./paper)	III For marking an answer book (Rs./script)	IV For marking Assignments (Rs./script)	V Counting Scripts (Rs./script)	VI Moderation (Rs./script)	VII For Viva-Voce	
						Per Candidate	Min.
U.G.	Rs. 200/-	Rs. 7/-	Rs. 4/-	Rs. 0.20 np	Rs. 15/-		
P.G. (including Professional Courses)	Rs. 200/-	Rs. 8/-	Rs. 5/-	Rs. 0.20 np	Rs. 20/-	Rs. 2.50	Rs. 50/-
Payment to the Chief Examiner		Rs. 200/- per session and Rs. 7/- per script for random check of 10% of scripts					
Coding & Decoding		Rs. 0.25 n.p. per script					
Conveyance		Rs. 100/- per day					
M. Phil		For valuing thesis Rs. 300/-				Rs. 75/-	
Ph.D.		Rs. 500/-				Rs. 150/-	

- b. If a Board of Examiners sets a question paper and evaluates the answer books, each external examiner shall be paid full remuneration specified in Columns (II), (III) above.
- c. When an answer book is examined by two external examiner jointly, each examiner shall be paid the full remuneration as specified in Column (III) above.
- d. In respect of a subject in which a question paper is set in two parts separately by two external examiners and the answer books thereof are also evaluated by them independently of each other, the remuneration payable to each examiner for setting the question paper and for evaluation of answer books shall be three-fifth of the rates specified in Column II, III for the paper and evaluation of answer books.
- e. If an external examiner examines answer books in respect of the question paper not set by him, he shall be paid for examining answer books at the rates as specified in Column (II) subject to a minimum fee equivalent to half the fee specified therein for setting a question paper for the examination concerned.
- f. If more than half of a question paper is changed by the Committee of Moderators, the Vice Chancellor may on the recommendation of the Convener of the Committee, direct that no remuneration be paid for setting the question paper.
- g. If two or more external examiners conduct the Viva-Voce, the remuneration shall be divided equally among them.
- h. The remuneration shall not be paid to external examiners until the Registrar has received the Award Sheets, the Answer Books, the Report of the Examiners and such other statements as they may be required to prepare.
- i. If the external examiners do not send in their complete document referred to in (h) above by the appointed date, the remuneration payable to them may be reduced by an amount calculated at Rs. 5/- per day for the first seven days of delay and Rs. 10/- per day thereafter, unless the Vice Chancellor is satisfied that the delay was due to cause beyond the control of Examiners.
- j. The remuneration payable to the examiners shall be as revised by the University from time to time.

Sd/- ILLEGIBLE  
Registrar